दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 03 जनवरी 2022 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 97

आज से लगेगी 15-18 साल के बच्चों को वैक्सीन, अब तक साढ़े 5.75 लाख से ज्यादा युवाओं ने कराया पंजीरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों की चिंता और खतरे को टालने के लिए सरकार की तरफ से तीन जनवरी से 15-18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बीच बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत रविवार शाम पांच बजे तक 5.75 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना पंजीकरण करा ल लिया है। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीन जनवरी यानि सोमवार से बच्चों के लिए वैक्सीन की डोज लगाने के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दी है।

कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बच्चे सुरक्षित हैं, देश का भविष्य सुरक्षित है! नए साल के अवसर पर, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। कोविन डाटा के अनुसार रविवार शाम पांच बजे तक 15-18 साल के 5.75 लाख से ज्यादा बच्चों ने पंजीकरण करा लिए हैं जिन्हें कल यानी सोमवार से टीका लगना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, 15-18 आयु वर्ग के अनुमानित 10 करोड़ बच्चे टीकाकरण के योग्य हैं।

बच्चों को लगेगी सिर्फ कोवाक्सिन की डोज

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जानकारी दी है कि 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को वर्तमान में केवल भारत बायोटेक कंपनी द्वारा तैयार की गई कोवाक्सिन की खुराक दी जाएगी। सभी टीकाकरण योग्य बच्चों को 1 जनवरी, 2022 से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके लिए सभी टीकाकरण योग्य बच्चों को 1 जनवरी, 2022 से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा 3 जनवरी 2022 से सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी पंजीकरण(रजिस्ट्रेशन) करा सकते हैं।

साल 2007 या उससे पहले पैदा हुए बच्चों को ही लगेगी वैक्सीन

सरकार की ओर से उम्र को लेकर जानकारी दी गई है कि साल 2007 या उससे पहले पैदा हुए बच्चों को ही फिलहाल कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। यह टीका 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। भारत बायोटेक की कोवाक्सिन बच्चों को दी जाएगी और दो खुराकों के बीच केवल 28 दिनों का अंतराल रहेगा। हालांकि कोवाक्सिन की दूसरी डोज व्यस्कों को भी 28 दिनों के बाद ही दी जा रही है।

बच्चों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा

केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 15-18 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा। टीकाकरण के प्रभाव को देखने के लिए बच्चों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा।

महत्वपूर्ण एवं खास

बस हादसे में तीन की मृत्यु, 28 घायल

आलिराजपुर (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के आलिराजपुर जिले के ग्राम चांदपुर में आज एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरने के कारण 03 यात्रियों की मृत्यु हो गयी और 28 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार तड़के हुए इस हादसे के बाद घायलों को यहां जिला अस्पताल में लाया गया है। सूत्रों ने कहा कि बस का स्टेयरिंग फेल होने की जानकारी सामने आयी है। इस वजह से गुजरात से आलिराजपुर जिले की ओर आ रही बस चांदपुर गांव के पास लखोदरा नदी में गिर गयी। यात्रियों की पहचान की जा रही है। बस को जेसीबी मशीन की मदद से राहत एवं बचाव दल की ओर से निकाला गया और घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया।

द. अफ्रीका के संसद भवन में लगी आग की लपटें राष्ट्रीय सभा तक पहुंची

केप टाउन । दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केपटाउन में संसद भवन में आज सुबह आग लग गई और यह इमारत में राष्ट्रीय सभा और निचले सदन तक पहुंच गई। सुरक्षा समिति के सदस्य जीन पिएरे ने बयान जारी कर बताया कि अग्निशमन विभाग को संसद मार्ग पर एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली, जोकि संसद क्षेत्र के अंदर थी। घटना की सूचना मिलते ही करीब 36 अग्निशमन कर्मी दमकलों सहित मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। संसद परिसर में सदियों पुरानी इमारतें मौजूद हैं।

ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.30 करोड़ के पार

लंदन। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,62,572 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही यहां इस महामारी से अब तक प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 1,31, 00,458 हो गयी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहां इस दौरान इस जानलेवा विषाणु से 154 मरीजों की मौत हुई। इसके बाद यहां कोविड-19 से अब तक जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,48,778 हो गयी है। मौजूदा समय में यहां 11,918 कोरोना मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं।

यूएई ने लगाया प्रतिबंध, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले नागरिक नहीं कर सकेंगे यात्रा

दुबई । कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने अपने उन नागरिकों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली हैं। यह प्रतिबंध यूएई में 10 जनवरी से लागू होगा। इसके अलावा यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि लोगों को विदेश यात्रा करने के लिए पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने के बाद भी बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता है। यात्रा करने योग्य होने के लिए बूस्टर डोज लेना आवश्यक है। हालांकि, यह प्रतिबंध चिकित्सा या मानवीय छूट वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। यूएई ने संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप में अत्यधिक संक्रामक हो चुके ओमिक्रॉन को देखते हुए इस तरह के प्रतिबंध की घोषणा की गई है। इसके अलावा कोरोना के मामलों में भी तेजी बढ़ोतरी हो रही है।

छत्तीसगढ़ से जंगों में ड्रोन से होगी हाथियों की निगरानी

भोपाल (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ से सटे मध्यप्रदेश के जंगलों में घूम रहे 70 से अधिक हाथियों की निगरानी अब ड्रोन से की जाएगी। वे बस्तियों और खेतों में रहने वाले किसान और उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तार फेंसिंग की जाएगी, जिसमें करंट छोड़ा जाएगा। सौर ऊर्जा से उत्पन्न यह करंट सिर्फ झटका देगा। हाथी दल के किसी एक हाथी को कालर आइडी भी लगाया जाएगा ताकि दल के विचरण की जानकारी मिल सके। प्रदेश में हाथियों के बढ़ते दखल को देखते हुए हाथी विशेषज्ञों ने यह सलाह दी है। भारत सरकार के हाथी विशेषज्ञ सहित असम व विभिन्न संस्थाओं के आधा दर्जन विशेषज्ञों ने पिछले दिनों हाथी प्रभावित क्षेत्रों में दो दिन गुजारने के बाद सुझाव दिए हैं। मध्यप्रदेश में हाथी बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं, साढ़े तीन साल से 45 हाथियों के एक दल ने बांधवगढ़ क्षेत्र में ढेरा डाल रखा है। इस अवधि में हाथियों ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचलकर मार डाला है। दो महीने पहले 25 हाथियों का एक और दल अनूपपुर के रास्ते मध्यप्रदेश में दाखिल हो गया है। धीरे-धीरे बढ़ रही हाथियों की समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने प्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की अध्यक्षता में हाथी विशेषज्ञों का एक दल गठित किया है। जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विश्व प्रकृति निधि संगठन, असम सहित अन्य विशेषज्ञ थे। उन्होंने बांधवगढ़ के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में दो दिन गुजारे हैं। अब यह दल सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। इन विशेषज्ञों ने जो सुझाव दिए हैं। उनके आधार पर लघु और दीर्घ अवधिक की योजना बनेगी। दीर्घ अवधि की योजना में मध्यप्रदेश को हाथी परियोजना में शामिल कराने का लक्ष्य रहेगा। इससे प्रदेश को हाथियों की निगरानी और नियंत्रण का तंत्र मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त राशि मलेगी।

आम आदमी पार्टी ने मांगा नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह का इस्तीफा

नई दिल्ली (आरएनएस) । राजन बाबू अस्पताल की जर्जर इमारत पर आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह का इस्तीफा मांगा है। 'आप' ने कहा कि राजा इकबाल सिंह को नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेयर राजा इकबाल सिंह बताएं कि अगर आप अपने वॉर्ड के अंतर्गत आने वाले राजन बाबू अस्पताल की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी नॉर्थ एमसीडी की देखभाल कैसे करेंगे। खुद भाजपा की स्टैंडिंग कमेटी ने माना इमारत खतरनाक फिर भी मरीजों का इलाज जारी, लेकिन मेयर राजा इकबाल सिंह झूठी बयानबाजी में व्यस्त। आम आदमा पार्टी के नेताओं ने कहा कि इससे पहले एमसीडी के अंतर्गत करोलबाग के अर्पित होटल हादसे में 17 मासूमों की, शास्त्री पार्क में एक इमारत गिरने से 67 लोगों की, चांदनी चौक में एक इमारत गिरने से 2 लोगों की, सावन पार्क हादसे में 7 लोगों की और 2021 में मलकागंज में इमारत गिरने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। हम भाजपा के नेताओं, मेयर और अध्यक्ष आदेश गुप्ता को चुनौती देते हैं कि साथ चलकर अस्पताल देखें, दिल्ली की जनता को वास्तविकता पता चल जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा है।उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने और 'आप' विधायक आतिशी जी ने जब आरबीटीबी अस्पताल का दौरा किया तो हमने पूरे सिलसिलेवार तरीके से वीडियो में दिखाया था कि कैसे पूरी इमारत चारो तरफ जर्जर हो चुकी है।

देश में कोरोना मामलों में आया बड़ा उछाल

» 24 घंटे में 27,553 नए मामले, 284 मरीजों की मौत

» ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर डेढ़ हजार के पार

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना मामलों की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है उससे तीसरी लहर की दस्तक भले ही देर से लेकिन भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान संक्रमण से 284 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं ओमिक्रॉन वैरिएंट के भी मामले बढ़कर 1,525 हो गये हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मसलन संक्रमित मरीजों में रोजाना लगभग पांच हजार की बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,553 मामले सामने आए हैं। इसमें मुंबई में 6347, दिल्ली में 2716 और कोलकाता में 2398 मामले सामने आए। जबकि ओमिक्रॉन वैरिएंट से 1,525 लोग संक्रमित हुए हैं। इस दौरान 284 लोगों की मौत हुई है। चिंता करने वाली बात यह है कि देश में सक्रिय मामले बढ़ने लगे हैं। ताजा आंकड़े के अनुसार देश में कुल सक्रिय मामले 1,22,801 हो गए हैं। वहीं इस दौरान केवल 9,249 लोग ही स्वस्थ हो पाए।

ओमिक्रॉन के मामले 1500 के पार

पूरे देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1525 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इसके कुल 23 राज्यों में दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में जहां सबसे अधिक 460 मामले हैं वहीं 351 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली है। अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु (117), गुजरात(136), केरल (109), राजस्थान (69), तेलंगाना(67), हरियाणा (63), कर्नाटक (64), आंध्र प्रदेश (17), पश्चिम बंगाल(20), ओडिशा (14), मध्य प्रदेश (9), उत्तर प्रदेश (8), उत्तराखंड (4), चंडीगढ़ (3), जम्मू-कश्मीर (3), अंडमान एवं निकोबार (2), गोवा (1), हिमाचल प्रदेश (1), लद्दाख (1), मणिपुर (1) और पंजाब में 1 मामला दर्ज किया गया है।

खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ सीडीएस रावत का चॉपर

» महीने भर बाद आई रिपोर्ट में हुआ खुलासा : सूत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। तमिलनाडु में पिछले आठ दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोगों की मौत के करीब एक महीने बाद इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस घटना की जांच के लिए गठित की गई समिति के हवाले से सूत्रों ने बताया है कि ऐसा हो सकता है कि खराब मौसम के चलते ही यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। जांच समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और हाल ही में यह संभावना भी जताई गई थी कि जल्द ही इसका कारण सामने आएगा।

दरअसल, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य अधिकारियों की दुर्घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और यह जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि जांच या उसकी रिपोर्ट पर ना तो वायु सेना और ना ही सरकार ने अभी तक कोई बयान दिया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि दुर्घटना का कारण खराब मौसम हो सकता है। इस पर भी अब तक कोई बयान या स्पष्टीकरण नहीं आया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली जांच टीम ने हादसे के लिए जिम्मेदार संभावित मानवीय त्रुटि सहित सभी संभावित पहलुओं की छानबीन की है। विशेषज्ञों ने यह भी जांच की है कि जब हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी कर रहा था, तब चालक दल के दिशाभ्रमित होने का कहीं यह मामला तो नहीं है। इस बारे में जल्द ही आधिकारिक खुलासा हो सकता है।

फिलहाल कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के निष्कर्ष और उसके द्वारा अपनाई गई प्रकिया की कानूनी पड़ताल की जा रही है। कानूनी पड़ताल यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि जांच टीम ने सभी निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन किया हो। उधर हादसे के संभावित कारणों के बारे में पूछे जाने पर कई विमानन विशेषज्ञों ने कहा है कि पायलट के परिस्थितिजन्य जागरूकता खोने से दृश्य भ्रम होने पर कई हवाई दुर्घटनाएं होने के उदाहरण हैं। बता दें कि दिसंबर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य अफसरों और सहयोगियों के साथ मौत हो गई। तमिलनाडु के सुलूर एयर बेस से वायुसेना के मी-17वी5 हेलिकॉप्टर से ऊंटी के करीब वेलिंग्टन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जाते समय उनका हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

पाक ने तालिबान को डुरंड लाइन पर बाड़बंदी करने से रोका, सेना को भी खदेड़ा

काबुल। अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान द्वारा पाकिस्तानी सेना को बाड़बंदी व सैन्य चौकी निर्माण से रोकने के साथ ही दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी डुरंड लाइन का विवाद फिर उभर आया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान शासन के दौरान यह मुद्दा सुलझा लिया गया है। अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा कराई जा रही बाड़बंदी व सैन्य चौकी निर्माण को तालिबान ने रोक दिया। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान सीमा में 15 किलोमीटर भीतर घुस आई थी और निर्माण करवा रही थी। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत स्थित चाहर बुर्जक जिले में सैन्य चौकी के निर्माण का प्रयास कर रही थी। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि एक हफ्ते पहले 22 दिसंबर को ही तालिबान के खुफिया महानिदेशालय के प्रांतीय प्रमुख ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी नांगरहार में की जा रही बाड़बंदी को रोक दिया था।

इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी (आई एफ एफ आर एएस) ने कहा कि यह एक ज्वलंत विवाद है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण है। 2600 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

पीएम मोदी के त्रिपुरा दौरे से पहले बीएसएफ अलर्ट, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिपुरा दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राज्य सरकार की तैयारी के अलावा भारत-बांग्लासदेश सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर सीमा अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी 4 जनवरी को त्रिपुरा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर राजधानी अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ आला-अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। बीएसएफ की 120 बटालियन के कमांडेंट रत्नेश कुमार ने कहा, 'जब भी वीवीआईपी लोगों का दौरा होता है, तो कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए सतर्कता बढ़ा दी जाती है। इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी गई है।'

भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री अगरतला के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ, महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल देने वाला है। गौरतलब है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के लिए त्रिपुरा आएंगे।

सीएम देव ने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नये एकीकृत टर्मिनल इमारत (एनआईटीबी) का निर्माण 3,400 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में नहीं बदलेंगे इडब्लूएस कोटे के मानदंड, केंद्र ने कमेटी की बात मानी

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीट पीजी काउंसलिंग के इडब्लूएस कोटे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने नीट पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के लिए 8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है, जबकि समिति द्वारा सुझाए गए संशोधित मानदंडों को अगले प्रवेश चक्र से अपनाया जा सकता है।

सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया, केंद्र सरकार ने नए मानदंडों को संभावित रूप से लागू करने की सिफारिश सहित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है। केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन तब किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए 8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययन किया था या नहीं, को लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई थी। केंद्र सरकार ने बाद में 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव कर रही है। इसके बाद उन्होंने इसके लिए कमेटी का गठन किया।

हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया है कि अब तक, मौजूदा ईडब्ल्यूएस मानदंडों को जारी रखना आदर्श है क्योंकि इसे बीच में बदलने से अनावश्यक जटिलताएं हो सकती हैं। यह आगे उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इसका मतलब यह होगा कि संशोधित ईडब्ल्यूएस मानदंड अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होने की संभावना है।

नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 6 जनवरी, 2022 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, जब तक कि कोर्ट की ओर से सुनवाई टाली न जाए।